



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2032]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2015/भाद्र 30, 1937

No. 2032]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015/BHADRA 30, 1937

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015

**का.आ. 2581(अ).**—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का. आ. 465(अ), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा वंसधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतर्राज्यिक वंसधारा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण को तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अपनी रिपोर्ट और यथा अपेक्षित विनिश्चय को तारीख 23 फरवरी 2013 को या उससे पूर्व देना अपेक्षित है ;

केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का. आ. 496(अ), तारीख 22 फरवरी, 2013 द्वारा रिपोर्ट और निर्णय की प्रस्तुती की अवधि को 23 सितंबर, 2014 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था ;

और उक्त अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने के लिए अवधि 23, फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और बढ़ाने का अनुरोध किया था ;

और ओडिशा की सरकार सिविल रिट याचिका सं. 2006 का 443 में अर्न्तवर्ती आवेदन सं. 2013 का 8 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय सरकार को अधिकरण के गठन की तारीख 17 सितंबर, 2012 से संगणना का निदेश देने के लिए की गयी थी ;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13, दिसंबर, 2013 को मामले को सुनकर यह आदेश पारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा ( 2) के अधीन यथा उपबंधित तीन वर्ष की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए वंसधारा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख के रूप में 17 सितंबर, 2012 की तारीख से अधिकरण को कृत्य करने के रूप में विचार किया जायेगा ;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का. आ. 778(अ), तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा निर्णय किया गया था कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 17 सितंबर, 2012 होगी और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन वंसधारा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और निर्णय के प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की अवधि 17 सितंबर, 2012 से प्रारंभ होगी ।

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने के लिए अवधि 17 सितंबर, 2015 से एक वर्ष की और बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वंसधारा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और निर्णय की प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 17 सितंबर, 2015 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित करती है ।

[फा. सं. 18/3 / 2013-बी.एम.]

डा. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव (पीपी)

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND  
GANGA REJUVENATION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2015

**S.O. 2581(E).**—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24<sup>th</sup> February, 2010 *vide* notification number S.O. 465(E), dated the 24<sup>th</sup> February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State River Vansadhara, and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, on or before the 23<sup>rd</sup> February, 2013 ;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 23<sup>rd</sup> February, 2013 ;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 436(E), dated the 22<sup>nd</sup> February, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year upto 23<sup>rd</sup> February, 2014 ;

And whereas, the Government of Odisha approached the Hon'ble Supreme Court *vide* Interlocutory Application No. 8 of 2013 in Writ Petition (C) No. 443 of 2006 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as 17<sup>th</sup> September, 2012 ;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter and passed the order on 13<sup>th</sup> December, 2013 that as the Tribunal started functioning with effect from 17<sup>th</sup> September, 2012, that date be considered as the effective date of the constitution of the Vansadhara Water Disputes Tribunal for the purpose of calculating the period of three years as provided under sub-section (2) of section 5 of the said Act;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 778(E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2014, had decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be 17<sup>th</sup> September, 2012, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the period of three years for submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal shall commence from the 17<sup>th</sup> September, 2012.

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from 17<sup>th</sup> September, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal for a period of one year with effect from the 17<sup>th</sup> day of September, 2015.

[F. No. 18/3/2013-BM]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy. (PP)